जरूरत कृषि अनुसंधान की पुनर्कल्पना की : डॉ. आर एस परोदा

वीडी न्यूज

देशभर के कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और आईसीएआर संस्थानों के निदेशकों के 20 मई को पूसा, दिल्ली स्थित सुब्रमण्यम सभागार में हुए वार्षिक सम्मेलन का केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुभारंभ किया।

इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री भागीरथ चौधरी, आईसीएआर के महानिदेशक डॉ. एम. एल. जाट तथा अधिकारीगण की उपस्थिति में कृषि शिक्षा, विस्तार और अनुसंधान के विषयों पर विस्तृत चर्चा में नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम के री-इमेजिनिंग पर देश के जाने माने कृषि विशेषज्ञ डॉ. आर एस परोदा ने पर अपने विचार रखे।

उन्होंने कहा कि भारत के नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम ने अब तक जो कुछ हासिल किया है वह रिसर्च सिस्टम के री-इमेजिनिंग के चलते ही संभव हो पाया, आज कई विकासशील देशों में भारत के नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम की चर्चा होती है जो बहुत सुदृढ़ है और बहुत आगे पहुंचा है। इसने हरित, श्वेत, नीली और रेनबो रिवॉल्यूशन की उपलब्धियां हासिल की हैं। आज हम विश्व में पांचवी इकॉनमी बन गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनाने का सपना तभी संभव हो पाएगा, जब कृषि फाइव ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी में एक ट्रिलियन का योगदान दे।

आज हमारा सिस्टम बहुत स्ट्रांग है यह इसलिए संभव हुआ कि इसमें पॉलिसी सपोर्ट रहा इसमें हमने इंस्टीट्यूशन बनाए और हमारे पास सक्षम ह्यूमन रिसोर्स भी है, इसी कारण आज हम आगे बढ़ पाए हैं इनमें 113 कृषि अनुसंधान संस्थान, 74 कृषि विश्वविद्यालय और 731 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। इस तरह का सुदृढ़ ढांचा कहीं और संभव ना हुआ है ना होगा, इसकी नकल पाकिस्तान ने नेपाल ने बांग्लादेश ने श्रीलंका ने और फिलीपींस ने भी की है। हमने रिफॉर्म लाकर इस सिस्टम को बहुत स्ट्रांग बनाया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद चार साल बाद 2029 में अपनी शताब्दी मनाने जा रहा है और इस अवधि में इसमें दो बार रिफॉर्म हुए हैं, एक रिफॉर्म 65 में हुआ जब डॉक्टर बीपी पाल पहले डायरेक्टर जनरल बनाए गए। दूसरा रिफॉर्म गजेंद्रगडकर कमीशन के तहत भारत रत्न और उस समय के कृषि मंत्री सी सुब्रमण्यम के कार्यकाल में आईसीएआर के पुनर्गठन के रूप में हुआ और उसमें डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन की स्थापना हुई और डायरेक्टर जनरल आईसीएआर को भारत सरकार के सेक्रेटरी का भी दर्जा दिया गया। यह एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी।

मैं समझता हूं कि इसी के तहत हम बहुत आगे बढ़ पाए हैं, आज हमारी कृषि में जो उन्नति हुई है उसकी सभी सराहना करते हैं। एक्सपोर्ट में हम 55 मिलियन यूएस डॉलर तक का एक्सपोर्ट कर पाए हैं, शीघ्र ही हम 100 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट कर सकेंगे।

युवा पीढ़ी को कृषि के प्रति मोटिवेट और अट्रैक्ट करना होगा

अब हमें जरूरत है कि इस सिस्टम की पुनर्कल्पना या री-इमेजिनिंग की। री-इमेजिनिंग के लिए हमें नए तरीके से सोचना होगा। सिस्टम को और सुदृढ़ और सक्षम बनाना होगा, एफिशिएंसी लानी होगी और इसके साथ-साथ रिफॉर्म्स भी लाने होंगे और सिस्टम को सपोर्ट के लिए और फंडिंग की भी आवश्यकता होगी। बहुत सालों से कम से कम दो शतक से डिमांड रही है कि एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम में हम और देशों से कम खर्च कर रहे हैं। अभी तक एग्रीकल्चर जीडीपी के 4 प्रतिशत इस पर खर्च हो रहा है, जबकि और विकसित देश 5 प्रतिशत तक खर्च करते हैं तो हमें इसको एटलीस्ट डबल करना होगा। हमें एक पैराडाइम शिफ्ट लाना है और वो पैराडाइम शिफ्ट है एग्रीकल्चर रिसर्च फॉर डेवलपमेंट नहीं अब एग्रीकल्चर रिसर्च फॉर इनोवेशन फॉर डेवलपमेंट।

अब नवाचार और इनोवेशन पर ज्यादा जोर देना होगा इनोवेशंस को किसानों तक पहुंचाना होगा और उसके लिए हमारी शिक्षा प्रणाली है उसमें भी वाइट कॉलर जॉब के अलावा हमें युवाओं को और सक्षम करना होगा ताकि वे एक्सटेंशन एजेंट बन सके इनपुट प्रोवाइडर बन सकें और एंटरप्रेन्योर भी बन सके एफपीओस पर जो जोर दिया जा रहा है और अब जितने भी इनोवेशन हुए हैं वो इनोवेशन किसान की लागत को कम करेंगे मेरा विचार है कि हमें उस तरफ और बढ़ना होगा - चाहे बायोपेस्टिसाइड है या बायो-फर्टिलाइजर है या माइक्रोइरीगेशन है चाहे वो फर्टिगेशन है बुहत कुछ संभावनाएं हैं युवा पीढ़ी को जो है सक्षम करने के लिए हमें कृषि के प्रति मोटिवेट और अट्रैक्ट करना होगा, किसान को आगे लाना होगा।

एक पैराडाइम शिफ्ट यह भी है कि एग्रीकल्चर रिसर्च फॉर नॉट दी इंटरेस्ट ऑफ साइंटिस्ट अलोन बट टू सर्व दी फार्मर्स की तरफ जाना होगा किसान को प्रधान बनाना होगा और उसके लिए हमें रिसर्च एजेंडा को भी रीओरिएंट करने की आवश्यकता है। साइंस बेस्ड एंड रिसर्च पेपर ओरिएंटेड एजेंडा के साथ अब हमें इनोवेशन ओरिएंटेड रिसर्च एजेंडा को आगे लाना है, युवाओं को सक्षम करना है और इसके लिए कई और अब ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट रिफॉर्म की आवश्यकता है।

इसमें कई रिपोर्ट्स दी जा चुकी हैं, डॉक्टर स्वामीनाथन रिपोर्ट भी थी डॉक्टर मशेलकर रिपोर्ट भी है डॉक्टर जीवीके राव रिपोर्ट भी है और मेरे द्वारा भी तीन चार रिपोर्ट्स एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस पर है एग्रीकल्चर रिसर्च रिक्रूटमेंट बोर्ड पर है एएसआरबी पर और कृषि विज्ञान केंद्र पर है उन सबको हमें लागू करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों को सिर्फ नॉट ओनली सेंटर्स फॉर फ्रंट लाइन डेमोंस्ट्रेशन बट सेंटर्स फॉर नॉलेज डिसेमिनेशन स्किल डेवलपमेंट और उसके साथ-साथ इनोवेशंस के ऊपर जोर देने के लिए हमें आगे बढ़ाना होगा।

यूनिवर्सिटीज को और स्ट्रांग करना होगा

कोऑर्डिनेशन कन्वर्जेंस की आवश्यकता है और मैं समझता हूं कि ऑलरेडी हमारा नेशनल एग्रीकल्चर सिस्टम बहुत आगे है सारी यूनिवर्सिटीज मिलकर काम करती हैं, यूनिवर्सिटीज को भी हमें और स्ट्रांग करना होगा और वर्ल्ड बैंक का एक नया प्रोजेक्ट लाने की भी आवश्यकता है। इस तरफ भी हमें ध्यान देने की जरूरत होगी, हमें मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन की आवश्यकता है जो प्रोजेक्ट बहुत सालों तक चल रहे हैं उनमें क्या सुधार लाया जा सकता है। हमें यह भी देखना होगा कि हम इनोवेशंस को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं सब्सिडीज को इंसेंटिव्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और इसके अलावा जो रिवार्ड एंड इंसेंटिव सिस्टम है जो हमारी डॉक्टर जल कमेटी की रिकमेंडेशंस है उनको फिर दोबारा एक बार देखना होगा और उसके द्वारा जो है वो सक्षम करने की आवश्यकता है। संस्थानों में कॉरपोरेट कल्चर लाना होगा और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देने की आवश्यकता होगी। हम आगे बढ़ने के लिए चाहेंगे कि हमारे नए आविष्कार किसानों तक पहुंचे, उसके लिए मिशन ओरिएंटेड प्रोग्राम हों और उनकी मॉनिटरिंग, उनको सपोर्ट दिया जाए और उनके द्वारा हम विकसित भारत की तरफ पहुंचे। यह संभव है इसमें चाहिए आपका सहयोग आपका योगदान जैसे पहले पॉलिसी सपोर्ट रहा।

नई साइंस को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, यूनिवर्सिटीज और जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज को और फ्रीडम एकेडमिक फ्रीडम की आवश्यकता है। जरूरत है कि हम नै सोच के साथ आगे बढ़ें, हमें आउट ऑफ ऑफ सोचना होगा और हमें थिंक ग्लोबली बट एक्ट लोकली के मुताबिक एक्ट करने की आवश्यकता है। जो ढांचा अब तक तैयार हुआ है इसका विकसित भारत के लिए बहुत योगदान रहेगा, हमें इसे नर्चर करना है इसके लिए सभी का योगदान आवश्यक होगा।